**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3499**

**26 मार्च, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**वस्त्र/कपड़ा उद्योग में नौकरियां**

**3499. श्री पि॰ भट्टाचार्यः**

**श्री दर्शन सिंह यादवः**

**श्रीमती रजनी पाटिलः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह धारणा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि नौकरी विहीन वृद्धि रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वस्त्र और कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है, जिसमें अपेक्षाकृत सीमित निवेश से अच्छी नौकरियां सृजित की जा सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र और कपड़ा उद्योग को सरकार द्वारा कम महत्व दिया जा रहा है और यदि हां, तो

इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस उद्योग की मदद करने के लिए मशीनों को आधुनिक बनाने तथा अत्याधुनिक सुविधाएं देने की आवश्यकता है और यदि हां, तो इस संबंध में तथा वस्त्र उद्योग में अधिक नौकरियां सृजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के आंकड़े दर्शाते हैं कि वस्‍त्र सहित संगठित क्षेत्र में रोजगार वर्ष 2013-14 में 135,38,114 की तुलना में 2.5% **की वृद्धि से बढ़कर वर्ष**  2014-15 में 138,81,386 **हो गया है।**

एएसआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2014-15 में वस्‍त्र एवं अपैरल का 0.11 का श्रम-पूंजी अनुपात (जो *लाख रुपए में निवेश की गई पूंजी द्वारा कुल कार्यरत लोगों का विभाजन है*) तुलनात्‍मक रूप से 0.4 के कुल फैक्‍ट्री औसत से अधिक है जिससे यह स्‍पष्‍ट होता है कि प्रति इकाई निवेश की रोजगार सृजन क्षमता वस्‍त्र क्षेत्र के अनुकूल है।

***(ग) से (घ):*** *वस्‍त्र उद्योग, के**देश में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा स्रोत होने के कारण सरकार ने एकीकृत वस्‍त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के माध्‍यम से सर्वश्रेष्‍ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करने; संशोधित प्रौद्योगिकी उन्‍नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के माध्‍यम से प्रौद्योगिकी उन्‍नयन करने, एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के माध्‍यम से कौशल में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ हथकरघा, हस्‍तशिल्‍प, रेशम, कपास, ऊन तथा पटसन के विकास के लिए सहायता प्रदान करने पर बल दिया है।*

 *परिधान तथा मेड-अप्‍स क्षेत्र में महिला केंद्रित रोजगार की अधिक क्षमता को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए* (i) *प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्‍साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई),* (ii) *राज्‍य लेवियों में छूट योजना (आरओएसएल) तथा* (iii) *परिधान तथा मेड-अप्‍स के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्‍नयन निधि योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सब्सिडी को शामिल करते हुए 6000 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज की भी शुरूआत की है।*

*\*\*\*\*\**